प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

16.10.2025 / प्रादेशिक समाचार / 9.20 बजे

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का योगदान हमारी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिमला में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार कार्य के दौरान दुर्घटना में चोटिल होने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाकर मुआवजा देगी और पूर्व में चोटिल हुए कर्मचारियों को भी इस नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों की पदोन्नति लंबित है, उन्हें भी पूरा हक दिया जाएगा।

जो आउटसोर्स कर्मचारी जिन्हें एक्सीडेंट होने के कारण चोट पहुंचती है, हमारी सरकार उन्हें मुआवजा देने की नीति लेकर आएगी और जो पिछले जितने भी ओउटसोर्स कर्मचारी जो बिजली का काम करते हुए जिन्हें चोट पहुंची है, उन सभी को मुआवजे की राशि आने वाले समय में प्रदान की जाएगी। जितनी प्रमोशनज हुई हैं, जो एएलएम की सचिवालय के कार्यालय में पड़ी है, मैं चाहता हूं उनकी प्रमोशन तत्तकाल प्रभाव से कर दी जाए।

वाइल्ड फ्लावर हॉल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और महत्त्वपूर्ण कानूनी सफलता प्राप्त की है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति से 401 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता–

डिस्पैच–योगराज शर्मा

वीओ– राज्य सरकार को शिमला के समीप मशोबरा स्थित रिजॉर्ट लिमिटेड कंपनी वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति से 4 सौ एक करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। अब हिमाचल इस कंपनी का एकमात्र स्वामी बन जाएगा। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि राज्य संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के बैंक में जमा राशि, शेयर होल्डिंग्स और पूंजी के विरुद्ध अग्रिम राशि के 50 प्रतिशत का हिमाचल प्रदेश मालिक बन गया है। उच्च न्यायालय के 14 अक्टूबर, 2025 के निर्णय के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनी के लगभग 3 सौ 20 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस राज्य को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दोहराया कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी और किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।

अग्निहोत्री /

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में लगभग 2 सौ 50 करोड़ रुपये की लागत से भव्य भवन निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है। अग्निहोत्री ने कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के लिए केन्द्र सरकार की ''प्रसाद योजना' के तहत 56 करोड़ 26 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक विरासत को सुदृढ़ किया जा रहा है।

धनीराम शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने और लोगों को किफायती दरों पर विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सोलन विधानसभा क्षेत्र के ममलीग में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर के साथ नया ओपीडी और पीईटी खण्ड खोला गया है। उन्होंने कहा कि मरीजों को अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाणा और टांडा मेडिकल महाविद्यालय में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जा रही है।

रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा बेहतर भविष्य का आधार है और प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन कर रही है ताकि छात्र हर स्तर पर लाभान्वित हो सकें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षकों और विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की एक्सपोजर विज़िट करवा रही है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक परिवर्तन लाना है। वे सोलन के एक स्कूल के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर कसौली के विधयक विनोद सुल्तानपुरी भी उनके साथ मौजूद थे।

और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से.....

आज समाचार पत्रों ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की घोषणा से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है।

अमर उजाला की सुर्खी है–**हिमाचल के 3 लाख 62 हजार कर्मियों–पेंशनरों को 3 प्रतिशत डीए का तोहफा।** पंजाब केसरी के शब्द हैं–**कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता, दीवाली से पहले मिलेगा एरियर।** दैनिक जागरण का शीर्षक है–**सीएम की घोषणा के बाद अधिसूचना जारी, यूजीसी वेतनमान वाले कर्मचारी भी हकदार।** दैनिक भास्कर का कहना है–**वेतन में होगा 800 रूपये से आठ हजार रूपये का लाभ।** दिव्य हिमाचल लिखता है–**मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के कार्यक्रम में की घोषणा।** दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार–**डीए भुगतान से खजाने पर 450 करोड़ का अतिरिक्त बोझ।**

हिमाचल दस्तक ने खबर दी है–**हिमाचल सरकार ने जीती कानूनी लड़ाई, वाइड फलावार हॉल संपति से मिलेंगे 401 करोड़ रूपये।** आपका फैसला की सुर्खी है–**28 सरकारी स्कूलों का दर्जा घटाया, पौने 3 साल में 1 हजार 3 सौ 53 संस्थान बंद व मर्ज हुए।**

————————————